International Journal of Financial Management and Economics

P-ISSN: 2617-9210
E-ISSN: 2617-9229
IJFME 2025; 8(2): 263-265
www.theeconomicsjournal.com
Received: 19-05-2025
Accepted: 21-06-2025

डॉ. मंजरी मिश्रा
असि0प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
हे0नं0ब0राज0स्ना0महा0 नैनी,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. मंजरी मिश्रा
असि0प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
हे0नं0ब0राज0स्ना0महा0 नैनी,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

अमेरिकी टैरिफ दर का भारत पर प्रभाव : एक मूल्यांकन

डॉ. मंजरी मिश्रा

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26179210.2025.v8.i2.593

सारांश
प्रशुल्क वह कर है जो एक आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाने वाला कर है जो आमतौर पर 5 प्रतिशत तक होता है, लेकिन किसी देश द्वारा घरेलू उद्योगों अथवा उत्पादों के संरक्षण के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वर्ष 2025 में यह एक वैश्विक मुद्दा बन गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व की वस्तुओं पर रेसीपोकल टैक्स (जिस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर जितनी चुंगी या ड्यूटी लगायी है, अमेरिका द्वारा उस देश की वस्तुओं पर उतना ही कर लगाना) लगाने हेतु कहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यह भारत के लिए आर्थिक अवसर हो सकता है क्योंकि इसमें कृषि को छोड़कर के अन्य क्षेत्रों में विश्व बाजार हेतु खोलने का अवसर मिलेगा और घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा व गुणवत्ता बढ़ेगी। वहीं दूसरे प्रकार के अर्थशास्त्रियों का मत है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है और विकसित भारत का सपना खण्डित हो सकता है। साथ ही मुद्रास्फीति बढ़ सकता है और थ्क्ए थ्च् में कमी आ सकती है।

कूटशब्द : टैरिफ, रेसीपोकल टैक्स, मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला, आपदा।

प्रस्तावना
आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर या टैरिफ का भुगतान घरेलू आयातको को करना होता है। इसे सीमा शुल्क भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी देश के आयातित माल की सीमा पर लगाया जाने वाला कर है। सर्वप्रथम यह राजस्व सृजन का एक जरिया है, दूसरा यह घरेलू और स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं को ज्यादा किफायती बनाकर उन्हें बढ़ावा देकर अन्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। किन्तु कई अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत है कि टैरिफ बाजार को फायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है।[2]

टैरिफ मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं– विशिष्ट टैरिफ, मिश्रित टैरिफ, यथामूल्य (मूल्य के अनुसार) और टैरिफ दर कोटा। जब उत्पाद पर उसके मूल्य पर ध्यान दिये बिना एक विशिष्ट शुल्क लगाया जाता है जो कि उसकी इकाईयों की संख्या और वजन पर निर्भर करता है जैसे कोई देश एक जोड़ी जूते पर 15 रूपये व एक जैकेट पर 100 रूपये शुल्क लगा सकता है। दूसरा, मिश्रित शुल्क आयातित उत्पाद की इकाई और मूल्य पर निर्भर करता है। तीसरा, मूल्यानुसार टैरिफ उत्पाद के आयात मूल्य के आधार पर लागू होता है। इसकी गणना प्रतिशत के रूप में होती है। उदाहरण भारत अमेरिका की वस्तुओं पर 11 से 17 प्रतिशत का शुल्क लगाता है। चौथा टैरिफ दर कोटा निश्चित मात्रा तक आयातित वस्तुओं पर एक विशिष्ट टैरिफ दर लगाता है। जैसे कोई देश किसी विशिष्ट वस्तु पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाता है किन्तु जब विशिष्ट वस्तु की संख्या निश्चित संख्या से अधिक हो जाय तो टैरिफ दर बढ़ कर 20 प्रतिशत हो जाता है।[3]

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है और रूस से तेल खरीदने को लेकर जुर्माने के रूप में 25 प्रतिशत और टैरिफ लगाया गया है। इस घोषणा पर 27 अगस्त 2025 से अमल होना है। इस टैरिफ से भारत से अमेरिका को होने वाले 40 अरब डालर के व्यापार को निशाना बनाया गया है इससे देश के जी0डी0पी0 में लगभग 1 प्रतिशत की कमी आ सकती है और कपड़ा एवं रत्न जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में लाखो भारतीय महिलाओं के रोजगार को अस्थिर कर सकता है। रूस व यूक्रेन के युद्ध विराम में विफल ट्रम्प ने रूसी माल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध की चेतावनी दी। नाटो महासचिव मार्क रूटा ने तो चीन, भारत और ब्राजील को सीधे कहा कि चीन, भारत और ब्राजील रूस को युद्ध विराम हेतु राजी करें अन्यथा अमेरिकी प्रतिबन्ध हेतु तैयार रहे।[4] ट्रम्प का तर्क है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में तूल दे रहा है किन्तु यह बेतुका व हास्यास्पद तर्क है क्योंकि

रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीददार चीन है जिनके प्रति अमेरिका कठोर कदम नहीं उठा पा रहा है। यूरोप भी बड़ी मात्रा में रूस से गैस खरीदता है और खुद अमेरिका रूस से उर्वरक खरीद रहा है, इतना ही नहीं भारत रूस से जो कच्चा तेल लेता है उसके रिफाइन्ड उत्पादो के खरीददार में अमेरिका भी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारत पर होने वाले प्रभाव को लेकर अर्थशास्त्रियों के दो मत है। पहले मत का समर्थन करने वाले का मत विखण्डनात्मक है। पहला मत जिसे विखण्डनात्मक मत कहा जा सकता है, दूसरा कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यह आर्थिक अवसर हो सकता है। पहले नकारात्मक प्रकार के अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत अमेरिका को निर्यात अधिक करते हैं, भारत लगभग 35 मिलियन डालर सरप्लस रहता है। भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर चुंगी 11 से 17 तक होती है। इतनी दर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को टैरिफ किंग की भी संज्ञा दी जा चुकी है। किन्तु अमेरिकी द्वारा हमारी वस्तुओं पर 3–7 प्रतिशत की चुंगी लगाया जाता है। यदि चुंगी 25 प्रतिशत हो जायेगी तो सरप्लस नहीं रख पायेगा। इसके साथ हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ेगा और चालू खाता घाटा बढ़ेगा। इससे डालर की कमी आयेगी। इससे रूपये के मूल्य में गिरावट आयेगी। (2) इस चुंगी दर की वृद्धि से निवेश कम होगा, निवेशक थक्र व थ्च में कमी आयेगी। इससे मुद्रा युद्ध शुरू होगा, इसे ही अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉनसन ने इमहहंत जील छमपहीइवनत च्वसपबल कहा। (3) इस मुद्रा युद्ध से वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिलता है जिससे अपनी वस्तुओं को बेचने की होड़ लगी रहती है, 1960 व 1970 के दशक में इसको बहुत बढ़ावा मिला जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक देश के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। (4) तर्क यह है कि इससे प्रत्येक देश अपनी वस्तुओं पर चुंगी लगायेंगे और इससे उपभोक्ता की वस्तुओं के दाम बढ़ेगा। इससे मुद्रास्फीति होगी और बाहर से मुद्रास्फीति आयेगी। इन सबसे उत्पादन व रोजगार में गिरावट आयेगी।

अर्थशास्त्रियों का एक दूसरा समूह है जो इसे आर्थिक अवसर मानता है। यह रचनात्मक प्रभाव है उनका मानना है कि मोदी और ट्रम्प में अच्छे सम्बन्ध है, अतः दोनों देशों अर्थात् भारत व अमेरिका के मध्य व्यापार समझौता होने वाला है जब व्यापार समझौता हो जायेगा तो ये समस्याएं समाप्त हो जायेगी।

इन विचारको का मत है कि भारत की स्थिति अठारहवी शताब्दी के फ्रांस की तरह है अर्थात वे बहुत जल्द न तो सीखते है और न ही पुराना छोड़ते है। भारतीय संकटकाल में ही किसी नयी नीति को अपनाते है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीयो के समक्ष एक संकट तब आया था जब खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता नहीं थी। 1975 में भारत–पाक युद्ध में भारत ने पाक को शिकस्त दी, ऐसे में भारत को अमेरिका से च्स्-480 के तहत हम अमेरिका से गेहूँ की सहायता वार्षिक तौर पर ले रहे थे। भारत द्वारा पाक को शिकस्त दी गयी। इससे 'लिरल जॉनसन' ने एक नीति चलायी जिसे "ीपच थ्वत उवनजी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि एक–एक शिप अनाज तभी मिलेगा जब भारत अमेरिका को नीति को स्वीकार करेगा। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया जिसको उनके बाद स्वर्गीय इन्दिरा गाँधी ने आगे बढ़ाया और सी सुब्रामण्यम को खाद्य मंत्री बनाया इन्होंने हरित क्रान्ति दिशा दी। इस प्रकार यह भारत के लिए एक अवसर साबित हुआ और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गये।[5]

इन 'नवउदारवादी अर्थशास्त्रियों' का विचार है कि भारत ने अमेरिका के टैरिफ पर वार्ता करने का आश्वासन दिया है। इनका मत है कि भारत उदारीकरण, भूमण्डलीकरण की नीति अपनाकर विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। कुछ अर्थशास्त्री जैसे जगदीश भगवती का मत है कि भारत को अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए।[6] किन्तु व्यापार में टैरिफ व नॉन टैरिफ बाधाएं बहुत सी है। इससे आर्थिक उदारीकरण नहीं आ पाया है। इनका कहना है कि हम कृषि को छोड़कर अन्य क्षेत्र जैसे– मोटरवाहन, इलेक्ट्रानिक्स आदि को विश्व बाजार के लिए खोल सकते हैं। इससे भारतीय कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और गुणवत्ता भी आयेगी। हो सकता है कि अमेरिका के साथ थ्ज। ;थ्तमम ज्तंकम ।हतममउमदजद्ध पर हस्ताक्षर हो जाय और यदि अमेरिका के दबाव से कर में कमी करते हैं तो कर की कमी से उपभोक्ता आयातक व निर्यातक तीनों को लाभ होगा क्योंकि ड्यूटी की दर अधिक होने से लागत बढ़ जाता है और वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में महँगी हो जाती है। कर कम करने से व्यापार में बढ़ोत्तरी होगी।[7]

अर्थशास्त्रियों का वह समूह जो विन्ध्वसात्मक प्रभाव को मानता है, का तर्क होगा इससे घरेलू उद्योग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग बाजार से बाहर हो जायेंगे क्योंकि बाहर से वस्तुएं आसानी से घरेलू बाजार में आने लगेंगी। किन्तु दूसरे प्रकार के अर्थशास्त्री जो नवउदारवादी है का तर्क है कि इससे बाजार में गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगीं और हमारे उद्योग और अच्छे परिणाम देंगे। इससे मध्यवर्ती वस्तुओं की बाजार में मांग बढ़ेगी। मोदी जी की सरकार ने 'मेक इन इण्डिया, च्स्प् ;च्तवकनबजपवद स्पउपजमक प्दअमेजउमदजद्ध जैसे कार्यक्रम चलाये। इससे विनिर्माण उद्योग कुल सकल घरेलू उत्पाद में 15ः से 25ः तक ले जाने का लक्ष्य है। बाजार को खोलने से लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव हो पायेगी।[8]

दूसरा रचनात्मक लाभ यह होगा कि ै। ने कनाडा में मैक्सिको व चीन पर टैरिफ लगाया। ै। के बाजार में 50ः आयात इन तीन देशों से होता है। टैरिफ से इन देशों से ै। के सम्बन्ध खराब होंगे। अमेरिका में इन देशों से आयात में कमी आयेगी। इससे भारत इन देशों से आयात में आयी कमी को पूरा कर अपना प्रमुख स्थान बना सकता है।[9]

तीसरी लाभ यह होगा कि ै। के चुंगी के शिकार देशों अपना विकल्प खोजेंगे। जैसे यूरोपीय यूनियन का रूख भारत के थ्ज। के प्रति नरम हुआ। आस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया, जापान के साथ भारत के सम्बन्ध पहले से बहुत अच्छा है। न्।म्ए न्ज्ञ से हमारा थ्ज। हो जाये और भारत को बहुत फायदा होगा। इन देशों के साथ भारत के थ्ज। में बड़ी बाधा ड्यूटी का अधिक होना है। इस प्रकार हम भारत से अमेरिका के बाहर अपने व्यापार का विस्तार करेगा।[10]

चौथा अमेरिका व चीन से परेशान देश भारत में अपना भविष्य देखेंगे। वे भारत को डंदनबिजनतपदह ब्मदजतम के रूप में देखेंगे। चीन व भारत में नजदीकियां बढ़ेंगी, हाल ही में चीन के प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों के लिए चीन के बाजार को खोला जाना महत्वपूर्ण है, इतना ही नहीं सीमा व्यापार बढ़ाने, निवेश प्रवाह बढ़ाने, जल्द से जल्द सीधे उड़ान कनेक्टीविटी को फिर से खोलने के प्रस्ताव इस ओर संकेत करते हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्रीय व ट्रम्प समर्थक निक्की हेली ने भारत व अमेरिकी टैरिफ से भारत को विश्व का समर्थन बढ़ने और चीन व रूस से नजदीकी का अनदेखा जताया है।

निष्कर्ष

हम कह सकते हैं कि भारत अमेरिकी टैरिफ को बेअसर करने का भरसक प्रयास करें और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुधारो को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें जी0एस0टी0 में दो स्लैब कर सुधार किया। साथ चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को नरम करना, ई–कामर्स एक्सपोर्ट हब की शुरूआत करना, चमड़ा उद्योग के लिए पर्यावरण नियमों में छूट, तम्बाकू और फार्मा व्यापारी के पंजीयन नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ाना ओर औद्योगिक मंजूरी के पोर्टल को और अपडेट करना शामिल है। पुनः श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने वाले विभिन्न

कार्यक्रम जैसे कर्नाटक में शक्ति नामक मुफ्त सार्वजनिक बस सेवा, राजस्थान का इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना जिसमें महिला कार्यदिवस अधिक है, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गाँधी जी का कहना है कि 'किसी राष्ट्र की ताकत उसके महिलाओं में निहित होती है'। इन सब प्रयासों से लगता है कि अमेरिकी टैरिफ का यह भारत के लिए रचनात्मक प्रभाव साबित होगा। भारत को इस खेल में कूटनीटिक निपुणता के साथ चीन से मिलकर चलना होगा क्योंकि ट्रम्प उसी की सुनते हैं जिसके पास पलटवार की क्षमता होती है। चीन के पास पलटवार हेतु दुर्लभ खनिज है तो रूस के पास तेल व अनाज। भारत को अपनी कूटनीति पर ही दाव लगाना होगा।

सन्दर्भ

1. Shah, K.T.: Trade Tariff and Transport in India, Gyan Publishing House, First Addition 1 January 2025, Page 48.
2. Shah, K.T.: Trade Tariff and Transport in India, Gyan Publishing House, First Addition 1 January 2025, Page 50.
3. Nageshwaran V. Anant: The rise of Finance: Causes, consequences and cures First Addition 2019, Page 72-76.
4. Nageshwaran V. Anant: The rise of Finance: Causes, consequences and cures First Addition 2019, Page 91-92.
5. Bhagwati Jagdish: Free Trade in India, Princton University, First Addition 2002, Page 28-29.
6. Lahiri K. Ashok: India in Search of Glori: Political Calculus and Economics Penguin Publisher First Addition 23 January 2023, Page 162.
7. Bhagwati Jagdish: Free Trade in India, Princton University, First Addition 2002, Page 52-53.
8. लेख (विश्व के लिए खतरनाक होगा टैरिफ का दांव–बी.बी. सी. हिन्दी के पूर्व सम्पादक शिवकान्त वर्मा द्वारा) दैनिक जागरण 21 जुलाई 2025, पेज–7
9. Lahiri K. Ashok: India in Season of Glori: Political Calculus and Economics Penguin Publisher First Addition 23 January 2023, Page 174.
10. Subramanium Arvind: Counsel the challenges of Modi Jetaly Economics First Addition 2023, Page 132.